BSNL EMPLOYEES UNION
Central Head Quarters

BSNLEU
P. Abhimanyu
General Secretary

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union.
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

प्रेस वक्तव्य **दिनांक: 28.07.2022**

सरकार द्वारा घोषित रिवाइवल पैकेज पर BSNLEU के विचार। :

मंत्रिमंडल ने कल 27 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में बीएसएनएल के लिए दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। प्रेस सूचना ब्यूरो के बयान के माध्यम से सरकार ने सूचित किया है कि बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ।

कल घोषित पुनरुद्धार पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन है जिसके लिए सरकार 44,993 करोड़ रुपये खर्च करेगी । 23 अक्टूबर, 2019 को घोषित प्रथम पुनरुद्धार पैकेज में पहले ही सरकार ने कहा था कि सरकार बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए 23,814 करोड़ रुपये खर्च करेगी । फरवरी, 2022 में माननीय वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर दिए गए अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि बीएसएनएल के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 44,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे । अब, दूसरे पुनरुद्धार पैकेज में यह कहा गया है कि सरकार बीएसएनएल को 4G स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए 44,993 करोड़ रुपए खर्च करेगी । यदि हम यह सब एक साथ जोड़ते हैं तो सब मिलाके 1,12,807 करोड़ रुपए होंगे ।

सरकार की बार-बार घोषणाओं से इस देश की आम जनता को एक गलत संदेश दिया जा रहा है कि बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए करदाताओं के पैसे की एक बड़ी राशि बर्बाद की जा रही है । हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार ऐसा गलत संदेश क्यों भेज रही है ? वास्तव में, सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए करदाता के पैसे से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है या खर्च करने जा रहा है । वास्तव में स्पेक्ट्रम विपुल मात्रा में उपलब्ध है और सरकार इसका केवल एक हिस्सा बीएसएनएल को आवंटित कर रही है, जिसके लिए सरकार किसी को कोई भुगतान करने नहीं जा रही है ।

23 अक्टूबर, 2019 को सरकार द्वारा घोषित बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज अभी भी सिर्फ काग़ज़ पर ही रहा है । पहले रिवाइवल पैकेज के तहत सरकार ने केवल यही किया है कि वीआरएस के जरिए 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की गई । बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने की सरकार की घोषणा अभी भी कागजों में ही है । ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने बीएसएनएल को उस 4G स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी ।

बीएसएनएल को अपनी 4G सेवा शुरू करने से रोकने के लिए सरकार ने दो बड़े रोड-ब्लॉक बनाए हैं । पहला रोड-ब्लॉक बीएसएनएल के पहले से मौजूद उपकरणों के अपग्रेडेशन के लिए अनुमति से इनकार करना था । बीएसएनएल के पास लगभग 50,000 3G बीटीएस हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के जरिए 4G बीटीएस में बदला जा सकता है । लेकिन, सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। यदि इस अपग्रेडेशन की अनुमति दी जाती तो बीएसएनएल कम से कम 2 साल पहले अखिल भारतीय स्तर पर अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था।

सरकार द्वारा बनाया गया अगला रोड-ब्लॉक बीएसएनएल को वैश्विक विक्रेताओं से 4G उपकरण खरीदने की अनुमति से वंचित करना है, जैसा कि अन्य निजी दूरसंचार ऑपरेटरों, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया द्वारा किया जा रहा है। मार्च, 2020 में, बीएसएनएल ने 50,000 4G बीटीएस की खरीद के लिए एक निविदा जारी की। हालाँकि, सरकार ने बीएसएनएल को इस निविदा को रद्द करने के लिए मजबूर किया और निर्देश दिया कि, बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल भारतीय विक्रेताओं से खरीदना चाहिए, न कि वैश्विक विक्रेताओं से। अब, बीएसएनएल को 4G उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए टीसीएस की पहचान की गई है। लेकिन, आज तक टीसीएस यह साबित नहीं कर पाई है कि उसके पास बीएसएनएल को 4G उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक तकनीक है ।

आज, यहां तक कि अपनी 5G सेवा के आरंभ के लिए सभी निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपने उपकरणों को वैश्विक विक्रेताओं, जैसे, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग से खरीदने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। बीएसएनएल को अपनी 4G सेवा शुरू करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर बीएसएनएल को बराबरी का मौका देने से इनकार किया गया है ।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदलती है। जब तक बीएसएनएल अपनी तकनीक को समय पर अपग्रेड नहीं करता, तब तक उसके लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा । तमाम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विस का आरंभ करने की कगार पर हैं । हालाँकि, यह बहुत निराशाजनक है कि कल घोषित किए गए रिवाइवल पैकेज में बीएसएनएल की 5G सेवा आरंभ करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

रिवाइवल पैकेज में कहा गया है कि 4 साल की अवधि में सरकार बीएसएनएल के पूंजीगत व्यय के लिए 22,471 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यहां यह बताना उचित होगा कि सरकार को बीएसएनएल को 38,540 करोड़ रुपये चुकाने हैं, जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनो ने बीएसएनएल को इस पैसे की अदायगी की मांग को लेकर पहले ही कई आंदोलन किए हैं। इस प्रकार, इस रिवाइवल पैकेज से जो 22,471 करोड़ रुपये आएंगे, वह सरकार द्वारा बीएसएनएल को चुकाए जाने वाले बकाया से कम है ।

साल दर साल सरकार 'पेंशन कंट्रीब्यूशन' के भुगतान के नाम पर बीएसएनएल से अतिरिक्त पैसा छीन रही है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है, जो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है । दूरसंचार विभाग से बीएसएनएल में शामिल कर्मचारी सरकारी पेंशन के हकदार हैं, जिसके लिए बीएसएनएल को हर साल सरकार को पेंशन कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है । इस पेंशन कंट्रीब्यूशन की गणना बीएसएनएल कर्मचारियों के अधिकतम वेतनमान पर की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार के बाकी कर्मचारियों के मामले में, वास्तविक मूल वेतन पर पेंशन कंट्रीब्यूशन एकत्र किया जा रहा है। सभी यूनियंस और एसोसिएशन्स लगातार मांग कर रहे हैं कि पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर बीएसएनएल से अतिरिक्त धन की लूट को रोका जाए और पहले से अधिक एकत्र किए गए धन को बीएसएनएल को वापस किया जाए। लेकिन, इसके बारे में रिवाइवल पैकेज में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

रिवाइवल पैकेज में यह भी घोषणा की गई है कि सरकार बीएसएनएल को "वायबिलिटी गैप फंडिंग" के रूप में 13,789 करोड़ रुपये प्रदान करेगी । यह "वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है ? बीएसएनएल भारत सरकार की ओर से देश के पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है । ये परियोजनाएं बीएसएनएल के लिए व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हैं । इसलिए, बीएसएनएल को जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा करने में इस सेवा को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए । 2014-15 से 2019 की अवधि के लिए यह वायबिलिटी गैप फंडिंग 13,789 करोड़ रुपये आती है । बीएसएनएल को इस राशि का भुगतान अतिदेय हो गया है । यूनियंस और एसोसिएशन्स ने आंदोलन का आयोजन किया और इस पैसे की प्रतिपूर्ति की मांग है । अब, बीएसएनएल को इस पैसे की प्रतिपूर्ति को भी पुनरुद्धार पैकेज के एक घटक के रूप में दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं है।

रिवाइवल पैकेज के तहत सरकार बीएसएनएल को 40,399 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सॉवरेन गारंटी देगी इसके लिए बॉन्ड बाजार में जारी किए जाएंगे । इससे कंपनी को अपने वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इस पूरे 40,399 करोड़ रुपये, और उस पर ब्याज, बीएसएनएल को चुकाना होगा और यह करदाता के पैसे से चुकाया नहीं जा रहा है।

Annexure:

Details of the refund to be made by the government to BSNL.

		Rs. in Crore
1	Viability Gap Funding for Rural Telephony @Rs.1250 Crores per FY since 2014-15 onwards	13,789
2	Interest on Wimax Spectrum Surrendered	5,850
3	Surrender of CDMA Spectrum	2,472
4	Refund of Excess paid Pension Contribution	1,996
5	Government Projects – NOFN (BharatNet)	1,051
6	LWF Project	380
7	Providing Building/Office space/Staff quarters etc., to DoT	320
8	Providing Telecom Services to DoT	282
9	Staff related claims i.e., Salary of BSNL staff working/worked in DoT, Loans & Advances paid by BSNL to unabsorbed employees of DoT, Leave salary paid to DoT employees (unabsorbed) & LSPC paid during Leave period etc.	225
10	Reimbursement of Leave Encashment against DoT period in respect of absorbed employees.	11,998
11	Claims from USOF w.r.t. A&N, Lakshadweep, Assam	30
12	25,000 Wi-fi Hotspot Project	131
13	Viability Gap Funding for Amarnath Yatra	16
	Total receivable =	**38,540**

पा.आभमन्यु
महासचिव,
बीएसएनएल एम्पलोईज यूनियन
मोबाइल नंबर: 9868231113